किसान की आत्महत्या एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोधपत्र-समाजशास्त्र

* प्रा. बिरादर आर. एस.

आत्महत्या यह व्यक्ती का वैयक्तीक कार्य है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन प्रख्यात समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुर्खिमने इसे विरोध किया और कहा भआत्महत्या सामाजिक दबाव का परीणाम है। अपना ग्रंथ The Suicide मे आत्महत्या सिध्दांत का प्रतिपादन किया। इसमे आत्महत्या के प्रकार भी स्पष्ट किये है। अहंवादी आत्महत्या के प्रकार में कहा है की, व्यक्ती जब सामाजिक जीवन में भाग नही लेता तब आपने आपको मुल्यहीन महसुस करता है, खुद को समाज से दुर रखता और आत्महत्या करता है । अंतः उन्होने कहा है की, व्यक्ती आत्महत्या करने के लिए सामाजिक परिस्थितीही जबाबदार है। इस तरह भारतीय समाज में जो किसान आत्महत्या कर रहा है वह अहंवादी प्रकार (Egoistic suicide) मे आते है। भारत एक कृषिप्रधान राष्ट्र है। राष्ट्रीय आय में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2008 में 18 : प्रतिशत है । लेकिन कृषि के उपर जिनेवाली लोंगो की संख्या कम नही हुई। अभी 66 : प्रतिशत जनसंख्या खेतीपर आपनी अजिवीका निभाते है । भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले किसान के सामने आत्महत्या की मुशीबत खडी हुई है । भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था दोशयुक्त होने के कारण किसानों को आत्महत्या का सामना करना पड रहा है।

शोध के उददेश–(i) भारतीय किसानो के आत्महत्या की रूपरेखा स्पष्ट करना । (ii) किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में वैश्वीकरण की नीति, हरितक्रांती और ऋणमाफी योजना के असफलता की मिमांसा करना । (iii) प्राप्त तथ्यों के आधार पर निश्कर्श निकालना।

संशोधन पध्दती–इस शोध निबंध के लिए संपूर्ण भारतीय समाज कार्यक्षेत्र निश्चित किया है। उपर्युक्त उददेश्यों के अध्ययन के लिए व्दितीयक स्त्रोतो का अधिक सहयोग लिया है ।

विश्लेशणात्मक निर्वचनः–आत्महत्या की रूपरेखाः–भारत में वैश्वीकरण के नीति का अवलंब करने के बाद दस साल में कम से कम एक लक्ष 100000 किसानों ने आत्महत्या की है । किसान की आत्महत्या पंजाब, महाराष्ट्र कर्नाटक,तामिळनाडू और केरल जैसे प्रगत राज्यों में जादा हो रही है । जब की छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश ऐसे अप्रगत राज्यों में किसानों की आत्महत्या का प्रमाण कम है। महाराष्ट्र शासन के आदेश से गठीत की गई डॉ. नरेंद्र जाधव समिती के अनुसार 1997 से 2005 तक एक लक्ष पचास हजार ;150000द्ध किसानों ने आत्महत्या की है ऐसा दावा किया है । महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की तुलना में जादा से जादा किसान आत्महत्या कर रहे है। सन 2007 में 4238 किसानों ने आत्महत्या की है। अपने देश में प्रतिदिन 46 किसान आत्महत्या कर रहे है। 2007 में 16,332 किसानों ने आत्महत्या की है। देश में 2007 में सभी मिलकर 1,22,637 लोंगो ने आत्महत्या की है। उनमे 14.4 : प्रतिशत आत्महत्या करनेवाले किसान है।

वैश्वीकरण की नीतिः–वैश्वीकरण विश्वस्तरपर कियाशिल एक ऐसी प्रकिया है, जिसमें समय और स्थान की सीमाओं को तोडते हुए समुदायों और संगठनों को अन्योन्याश्रीतता और अन्तर्पास्परिकता में के संबंधो में बांधती है। ऍन्थोनी गिडेन्स के अनुसार भविश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधो को घनिश्ट बनाने का नाम ही वैश्वीकरण है। भारत ने सन 1991 में गॅट करार पे हस्ताक्षर करके वैश्वीकरण का अवलंब किया। गॅट करार के अनुसार देश के कृषि उत्पन्न के 10 : प्रतिशत सब्सिडी देणे की तरतुद है। अप्रेल 2000 में कृषि माल के आयात कर में कमी की। सन 1991–1992 में 300ः प्रतिशत आयात शुल्क था, लेकिन यह शुल्क 2006 के बजट में 12.5ः प्रतिशत कम किया गया।

उदाः–सन 2006 के बजट कें अनुसार अमरीकन कपास पर 150ः शुल्क लगाने के तरतुद थी, लेकीन केवल 10 : शुल्क लगाया गया। इस कारण भारत में कपास का मुल्य 2500 रू. क्विंटल से 1600 रू. क्विंटल तक कमी आयी। वैसे ही सोयाबीन पर 45ः शुल्क लगाने के बाद

* समाजशास्त्र विभाग, पीपल्स कॉलेज, नांदेड

मूल्य 1500 रू. से 800 तक कम हुआ। सन 1991–92 में 310 करोड रूपये की आयात होती थी, लेकिन सन 2003–2004 मे यह आयात 65,741 करोड रूपये तक बढ गयी। इस वजह से भारतीय किसानों के कृषि उत्पादन को सही मुल्य प्राप्त नही हो पा रहा है। वैश्वीकरण के नीति का अवलंब करने से पूर्व पंजाब मे सन 1982–83 मे हेक्टरी 7500 रूपये उत्पादन खर्च था। यह बढकर सन 1994–95 में 34,000 हजार रूपये तक बढ गया। भारत मे सन 1980–1990 के दशक में 2.29 : कृषि उत्पादन का वार्शिक वृध्दी दर 3.72: था, लेकीन सन 1991–2000 के दशक में इतना कम हुआ। अभी वह दर में 1.21: प्रतिशत कमी आयी। कृषि क्षेत्र का पूंजी निर्माण में हिस्सा सन 1987–88 में 11.7:प्रतिशत था, लेकिन इसमे सन 2000 में 7.2 : प्रतिशत तक कमी आयी । वैसे ही सन 1990 में कृषि का विकास दर 4.7 : प्रतिशत था, लेकिन वैश्वीकरण का स्विकार करने के बाद इसमें 2.3 : प्रतिशत तक कमी आयी। उपरोक्त सांख्यकिय विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है की कृषि क्षेत्र की स्थिती वैश्वीकरण का अवलंब करने से पूर्व अच्छी थी और अवलंब के बाद खराब हुई ।

हरीतक्रांती का अपयशः—हरीतकांती याने कृषि उत्पादन में बढोतरी करने के लिये कृषि के पारंपारीक तंत्र और यंत्र का त्याग कर के नये तंत्रो और यंत्रो का स्वीकार करना है। भारत मे सन 1967–68 में हरीतक्रांती का प्रारंभ हुआ। हरीतक्रांती से कृषि उत्पादन में बढोत्तरी हुई, लेकिन साथ–साथ उत्पादन खर्च भी बढ गया। खेती विरासत मिशन पंजाबश इस पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्था के कार्यकारी संचालक उमेंद्र दत्त लिखते है की, भहरीतक्रांती का सबसे जादा प्रभाव पडनेवाले पंजाब राज्य में हर किसान के उपर 22,000 ऋण का बोज है । पंजाब राज्य में प्रति हेक्टर जमीन पर 56,442 रूपये ऋण है। सन 2003 के भराष्टीय नमुना सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब राज्य के हर किसान के उपर 41,000 रूपये ऋण है। पंजाब कृषि विदयापिठश ने सन 2007 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब राज्य के हर किसान के उपर 92,000 हजार रूपये ऋण है। पंजाब जैसे प्रगत राज्य में किसानों की जैसी स्थिती है, वैसीही अन्य राज्यों में भी है। हरीतक्रांती से कृषि उत्पादन बढ गया, लेकिन साथ ही कृषि उत्पादन खर्च ही बढ गया। हरीत क्रांती से भारत में अनाज की जरूरत पुरी हुई, लेकिन किसान को उसका लाभ नही हुआ। इस कारण किसान आत्महत्या कर रहे है।

ऋणमाफी योजना का अपयशः—भारतीय कृषि क्षेत्रो को सहारा देणे के लिए वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने किसानों के 60 हजार करोड रूपये की ऋण माफ करने की घोषणा 29 फरवरी 2008 के आर्थिक बजट में की है। इस निर्णय से देश के छोटे और सिमान्त किसानों को नया जीवन मिल सकता है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है की जब किसान ऋण के बोज मे दबकर आत्महत्या कर रहे है। ऋणमाफी योजना 60 हजार करोड से 71,680 करोड तक बढ गयी है।

शोध–वैश्वीकरण के नीति का अवलंब करने से पूर्व कृषि का विकास दर, राष्टीय आय में कृषि का हिस्सा अधिक था। नीति के अवलंब के बाद इन सभी में कमी आयी। इसका अर्थ वैश्वीकरण से कृषि क्षेत्र का अधिक नुकसान हुआ। किसानो को मिलनेवाले सब्सिडी में कमी, Contract Base Farming, कृषि धान्यों की आयात , पेटंट के कारण किसानों की निर्भरता, इन सभी समस्याओं का निर्माण हुआ। इस वहज से किसानों को आत्महत्या करनी पड रहा है। ऋणमाफी योजना भी दोशयुक्त है। इस योजना में दो हेक्टर तक की भुमिवाले किसानो को ऋणमाफी के दायरें में रखा है।

निष्कर्ष–1. वैश्वीकरण की नीति किसानों की आत्महत्या का एक कारक है । 2. हरीतक्रांती के कारण किसानो को ऋणग्रस्तता का सामना करना पड रहा है । 3. ऋणमाफी योजनाश दोशयुक्त है ।

सुझाव–1. किसानों को रियायती दर पर साख की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। 2. देश में सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए । 3. श्रमप्रधान तकनीको अपनाया जाना चाहिए । 4. छोटे – छोटे किसानों को उन्नत बीज, खाद आदि आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए उदार शर्तो एवं दरों पर साख सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए । 5. कृषि क्षेत्र को मिलनेवाली सब्सिडी में बढोत्तरी की जानी चाहिए । 6. पायाभूत सुविधा; रास्ते, बिजली, दळण–वळण के साधन आदी में बढोत्तरी करनी चाहिए। 7. ऋणमाफी योजनाश में, भूमि की मर्यादा चार हेक्टर तक बढानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. हरीकृष्ण रावत, उच्चत्तर समाजशास्त्रीय विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन ,आगरा 2. प्रो.पि.सी.जैन एवं नरेंद्रकुमार, सामाजिक विचारों का इतिहासश,वि ाल प्रकाशन, दिल्ली. 3. नलिनी पंडीत–जागतिकीकरण आणि भारत. 4. Emile Durkhiem -‘The Suicied’ 5. Edited by Samitkar.- ‘Globalisation One Word Meny Voices’ 6. R.K. Mukharji.- ‘Research Methodology’7.हिन्दी मासिक–प्रतियोगिता दर्पनश 8. प्रा. अशोक नाईकवाडे शेतक–यांच्या आहत्महत्या–चिंता आणि चिंतन क्रिर्ती प्रकाशन, औरंगाबाद. 9. डॉ. जयप्रकाश मिश्र कृषि अर्थशास्त्र साहित्यभवन पब्लिकेशन, आगरा।